ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुआ 1150 बेड का

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज बनने से पहले यहां पर मात्र 200 बेड का अस्पताल होता था। इनमें से भी लगभग आधे बेड खाली ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त ईएसआई कवर्ड मज़दूर कम थे। यहां इलाज संतोषजनक न मिलने से मज़दूर आते नहीं थे। जब से मेडिकल कॉलेज बना है तब से यहां आने वाले मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 510 बेड से शुरू हुए इस अस्पताल में आज के दिन करीब 800 मरीज दाखिल रहते हैं। इसके अलावा करीब 400 बेड की कमी खल रही है।

जाहिर है यह सब अस्पताल द्वारा दी जा रही बेहतरीन सेवाओं के चलते है। पहले जहां प्राइमरी व सेकेन्डरी सेवाओं का भी अभाव था अब यहां सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। पूरे हरियाणा भर में इसकी सेवाओं का मुकाबला करने वाला कोई संस्थान नहीं है। हां, केवल दिल्ली स्थित एम्स इसका मुकाबला कर सकता है।

अस्पताल की उत्तम सेवाओं को प्राप्त करने के लिये मरीज़ों की बढ़ती संख्या के चलते बीते करीब दो वर्ष से अस्पताल के विस्तार की चर्चा चल रही थी। इस सप्ताह उस चर्चा को मूर्त रूप उस समय मिला जब कॉर्पोरेशन के चेयरमैन यानी केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव ने संस्थान के लिये 1150 बेड की स्वीकृति प्रदान कर दी। शीघ्र ही करीब 550 बेड की दस मंजिला बिल्डिंग के निर्माण कार्य शुरू होने की सम्भावना है।

1150 बेड के लिये कम से कम 750 स्टाफ़ नर्स, 40 सैम्पल लेने वाले, 60 लोग लैबोरेट्री में टेस्टिंग करने वाले, 33 छोटे-बड़े ऑपरेशन थियेटरों के लिये, 80 टेक्नीशियन, इतने ही सहायक टेक्नीशियन तथा 50 लोग अन्य ब्रांचों के लिये मिलेंगे।

आज के दिन जब अस्पताल की ओपीडी में प्रति दिन 4500 मरीज आ रहे हैं तथा 800 मरीज दाखिल हैं तो बमुश्किल 250 स्टाफ़ नर्स तथा आवश्यकता का एक चौथाई पैरामेडिकल स्टाफ़ मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन की मुख्यालय से पुरानी मांग रही है कि पदों की उक्त संख्या के अनुपात में उसे आज के कार्यभार के अनुरूप पैरामेडिकल स्टाफ़ उपलब्ध कराया जाए।

अस्पताल के नाम पर एक और बिल्डिंग बनाने की घोषणा

बल्लबगढ़ (मज़दूर मोर्चा) दस करोड़ की लागत से मेवला महाराजपुर में अस्पताल की तीन मंजिला बिल्डिंग बनाने के बाद अब सेक्टर दो में डेढ़ एकड़ के भू-खंड पर सात करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाने की तैयारी है। इसे 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बताया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को होने वाले फायदों को भी बढ़ा-चढ़ा कर गिनाया जा रहा है। नि:संदेह किसी भी छोटे-बड़े अस्पताल के बनने से स्थानीय लोगों को चिकित्सा सेवायें प्राप्त करने में काफ़ी सुविधा होती है। परन्तु यह सुविधा केवल बिल्डिंग के बन जाने से नहीं मिलती। इसके लिये बिल्डिंग में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ के साथ-साथ आवश्यक दवाओं तथा साजो-सामान का होना आवश्यक होता है।

हाल ही में गांव मेवला महाराजपुर में बने अस्पताल का उद्घाटन करके, पहले स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने अपने ही ग्रामवासियों को बेवकूफ़ बनाया और कुछ दिन बाद इसका श्रेय लेने को मुख्यमंत्री खट्टर भी उद्घाटन करने आ पहुंचे। इस सबके बावजूद अस्पताल में न तो पर्याप्त स्टाफ़ है और न ही कोई अन्य सुविधा। डिलीवरी कराने के लिये महिलाओं को पहले की तरह ही अब भी बीके अस्पताल तथा वहां से खदेड़े जाने के बाद जहां कहीं भी बात बने, पहुंचना पड़ता है। दस करोड़ की यह बिल्डिंग तो केवल चुनावों के दौरान मतदाताओं को दिखा कर वोट मांगने के लिये खड़ी की गई है। हां, दस करोड़ में से अधिकारियों ठेकेदारों व नेताओं को जो कमीशन मिल गया वह अतिरिक्त बोनस हो गया।

ज़िले भर में इस तरह की यह कोई अकेली बिल्डिंग नहीं है। सेक्टर 55 में दो एकड़ के भू-खंड पर बनी तीन मंजिला इमारत, सेक्टर 3 व 30 में भी बनी इतनी ही बड़ी इमारतें तो खड़ी है लेकिन डॉक्टरों व स्टाफ़ की कमी के कारण यहां आने वाले मरीजों, विशेष कर महिलाओं को धक्के ही मिलते हैं। इसी तरह ज़िले भर की तमाम छोटी-बड़ी डिस्पेंसरियों का भी यही हाल है। करीब दो वर्ष पूर्व तिगांव की छोटी डिस्पेंसरी (पीएचसी)को बड़ी डिस्पेंसरी (सीएचसी) बनाने के नाम पर बिल्डिंग तो अच्छी-खासी बना कर खड़ी कर दी लेकिन सुविधाओं के नाम पर निल बटा सन्नाटा। इसी शृंखला में सेक्टर दो की बिल्डिंग बनाकर लोगों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद भी जनता को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

सेक्टर 78 में विज्ञान भवन बनाने का राग पांच साल से अलाप रहे हैं

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) भाजपा सरकार का मूल मंत्र है, 'काम करने की बजाय केवल उसका शोर मचाओ'। न केवल फ़रीदाबाद बल्कि राज्य भर में खट्टर की भाजपाई सरकार अनेकों मेडिकल कॉलेज बनाने, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने, सड़कें बनाने, स्मार्ट सिटी बनाने और न जाने कितनी तरह के सब्जबाग जनता को दिखाती आ रही है। इन्हीं में से एक है नहर पार के सेक्टर 78 में आठ एकड़ के भू-खंड पर 427 करोड़ की लागत से आलीशान पंच सितारा विज्ञान भवन बनाने का। इसमें 200 कमरे, 25 लिफ्टें, दसियों एस्केलेटर, बड़े-बड़े कन्वेंशन हाल तथा इनमें बेहतरीन किस्म की लाइटें लगाई जायेंगी। हजारों गाड़ियों के लिये पार्किंग बनेगी।

जनता के भ्रम को मजबूत करने के लिये करीब पांच साल पहले इसका शिलान्यास भी खट्टर ने कर दिया था। इसके बावजूद यहां आज तक एक ईंट तक नहीं लगी है और न ही लगने की कोई सम्भावना आस-पास नजर आ रही है। हां, जनता की उम्मीद जगाये रखने के लिये समय-समय पर इस प्रोजेक्ट की याद जनता को दिलाते रहते हैं। इसके साथ-साथ इससे होने वाले सम्भावित फायदों का गुणगान करके सरकार अपनी पीठ ठोंकती रहती है। क्षेत्र के जानकार लोग बताते हैं कि इसका बजट, काम शुरू होने से पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है। इसी को तो कहते हैं काम बेशक न करो काम करने का दिखावा करते रहो।

टेस्ट के नाम पर लूटती हैं ठगीमार लेबोरेट्रीज

– पकड़े जाने पर लेबोरेट्रीज को लूटता है नेग्लिजेंस बोर्ड

– निजी लैब के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पुरुष के गर्भाशय, अंडाशय बताए गए

– बीके के डॉक्टरों ने यह कह कर लौटाया कि यहां महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होता है पुरुषों का नहीं

- मरीब मजदूर को हेपेटाइटिस बी संक्रमित होने की भी फर्जी जांच रिपोर्ट थमाई, काम छूटने से आर्थिक संकट से जूझ रहा परिवार

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बीके अस्पताल में करोड़ों रुपये खर्च कर डायग्नोस्टिक लैब बनाई गई है ताकि उसमें सभी तरह की जांचें हो सकें बावजूद इसके कमीशनखोर डॉक्टर बाहर से टेस्ट लिखते हैं। पचास प्रतिशत कमीशन देने वाली ये निजी लैब मरीजों को लूट कर मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती हैं। जागरुकता की कमी के कारण मरीज गलत रिपोर्ट की शिकायत नहीं करते, एक-आध शिकायत होती भी है तो नेग्लिजेंस बोर्ड मोटी वसूली करके अपनी जांच में सब कुछ ओके कर देता है। ऐसे ही एक मरीज को एक निजी लैब ने हेपेटाइटिस बी संक्रमित होने की झूठी रिपोर्ट थमा दी तो दूसरी लैब ने अल्ट्रासाउंड में उसके स्त्री जननांग होना बता दिया। जांच कर रहा नेग्लिजेंस बोर्ड भी मामले में लीपापोती करता नजर आ रहा है।

दिहाड़ी मजदूर राजू मूल रूप से मेवात का निवासी है, वह यहां नगला एंक्लेव पार्ट एक में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहा है। राजू के अनुसार उसके शरीर में दर्द रहता था। निजी चिकित्सक ने देखने के बाद उसे खून की जांच कराने की सलाह दी। डॉक्टर की सलाह पर राजू ने हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक (एचओडी) के कलेक्शन एजेंट राजवीर से 27 अप्रैल 2023 को संपर्क किया। आरोप है कि कलेक्शन एजेंट ने खून की कई जांचें अपनी तरफ से बढ़ाकर लिख दीं। शाम को रिपोर्ट आई जिसमें उसे हेपेटाइटिस बी का गंभीर संक्रमण होना बताया गया। निजी चिकित्सक ने उसे तुरंत ही बीके अस्पताल में दिखाने की सलाह दी।

बीके अस्पताल में डॉक्टर ने देखने के बाद कुछ टेस्ट और पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी, साथ में अर्जेंट भी लिख दिया। अस्पताल की लैब में जांच कराने पहुंचा तो बताया गया कि कुछ जांचें बाहर से करानी पड़ेंगी। बीके की अल्ट्रासाउंड लैब में बताया गया कि यहां केवल महिलाओं का ही अल्ट्रासाउंड होता है पुरुषों का नहीं। मजबूरी में उसने सारी जांच निजी लैब से कराने का निर्णय लिया।

उसने पवन हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करवाया जबकि एनसीआर डायग्नोस्टिक सेंटर से खून की जांच करवाई। 30 अप्रैल को आई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में राजू के गर्भाशय और दोनों अंडाशय सामान्य होना बताए गए जबकि यह महिला जननांग होते हैं। एनसीआर लैब से आई दूसरी खून की जांच में उसे हेपेटाइटिस संक्रमित नहीं होना बताया गया। गलत जांच रिपोर्ट के कारण मानसिक रूप से परेशान राजू ने इसकी शिकायत 1 मई को सीएमओ कार्यालय में की। सीएमओ ने इसकी जांच के लिए डॉ. दिनेश गुप्ता की अगुवाई में छह डॉक्टरों का नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया है। यह बोर्ड राजू की एमआरआई आदि कर मामले को दबाने में जुटा हुआ है।

औपचारिकता निभा रहा जांच बोर्ड

नेग्लिजेंस बोर्ड गलत काम करने वाले अस्पताल और लैबों से केवल वसूली करने का धंधा चला रहा है। आज तक इस बोर्ड ने किसी भी शिकायत में किसी भी अस्पताल या लैब के खिलाफ अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, न ही इसने किसी अस्पताल अथवा लैब का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की संस्तुति की है। राजू के अनुसार बोर्ड के सदस्यों ने उससे पहले ही एक सादे कागज पर दस्तखत करा लिए हैं। आशंका है कि बोर्ड के षडयंत्रकारी सदस्य एचओडी और पवन हॉस्टिपटल वालों को बचाने के लिए अपनी मनमाफिक रिपोर्ट बना कर राजू के हस्ताक्षर वाले सादे कागज पर जांच से संतुष्ट होना लिख कर मामला रफादफा कर देंगे।

गड़बड़ी करने वाले अस्पताल और लैब वाले तक जानते हैं कि मोटी कीमत देनी होगी और बोर्ड उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा या उनका कोई नुकसान नहीं होने देगा। मुट्ठी ही गर्म करनी है तो नोटिसों की परवाह भी नहीं की जाती, यही कारण है कि बोर्ड द्वारा भेजी गई पहली नोटिस का जवाब न तो एचओडी, न पवन हॉस्पिटल और न ही एनसीआर लैब वालों ने दिया। दूसरी नोटिस भेज कर सभी को नौ जून को दोबारा बुलाया गया। राजू और एचओडी का प्रतिनिधि तो आए लेकिन पवन हॉस्पिटल और एनसीआर लैब से कोई नहीं आया। बोर्ड के सदस्यों ने राजू का नाम पूछने और एक सादे कागज पर दस्तखत करवाने के बाद उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद एचओडी के प्रतिनिधि को बुलाकर कुछ देर बात हुई और वह भी चला गया। वहां मौजूद कुछ लोगों का दावा है कि बाहर निकलते समय एचओडी का प्रतिनिधि 21 लाख रुपये में सौदा पटने की बात कह रहा था। मजदूर मोर्चा इस दावे की पुष्टि नहीं करता लेकिन राजू ने बताया कि बोर्ड ने उसे दोबारा बुलाया ही नहीं। करीब ढाई घंटे इंतजार के बाद बयान दर्ज कराने के लिए वह खुद ही बोर्ड की बैठक में घुस गया तो पाया कि वहां कोई नहीं है। एक चपरासी ने बताया कि सभी डॉक्टर जा चुके हैं। वह सीएमओ के कार्यालय और वहां से उनके कैंप ऑफिस पहुंचा लेकिन दोनों जगहों से उसे भगा दिया गया। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार विभाग में चर्चा है कि अब राजू का एमआरआई आदि कर मामला समाप्त कर दिया जाएगा।

खराब रहती है व्यवस्था

कहने को तो सरकार हर तरह की जांचें सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होने के दावे करती है लेकिन अस्पताल में हमेशा किसी न किसी उपकरण के खराब होने, रीजेंट्स या केमिकल खत्म होने या स्टाफ के छुट्टी पर होने के कारण महत्वपूर्ण जांच नहीं हो पातीं और इस तरह मरीजों को बाहर से जांच कराने के लिए मजबूर किया जाता है। बाहर से जांच कराने का एक और बहाना है 'अर्जेंट'। पर्चे पर अर्जेंट लिखा देख बीके लैब वाले सामान्य से भी अधिक समय लगने की बात कहते हैं। मजबूरी में मरीज बाहर से जल्दी टेस्ट करवा लेता है। राजू के मामल में भी अर्जेंट जांच कराने की सलाह दी गई। जग जाहिर है कि जांच लिखने वाले डॉक्टर को निजी लैब पचास प्रतिशत तक कमीशन देती हैं, जो हर सप्ताह ईमानदारी से उन तक पहुंचा दिया जाता है। यह धंधा राजू का मामला सामने आने से पहले से चल रहा था और अभी भी जारी है। बीके अस्पताल के आस पास बहुत सी जांच लैब खुलने की वजह यही है कि मरीजों को ज्यादा दूर न जाना पड़े और डॉक्टरों को कमीशन भी जल्दी मिल सके।

पीड़ा सह रहा परिवार

पीड़ित राजू ने बताया कि हेपेटाइटिस बी संक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद साथी मजदूरों में उसके बीमार होने की बात फैल गई, अब संक्रमण फैलने के डर से कोई उसे काम नहीं दे रहा है। काम बंद होने से एक दिव्यांग सहित तीन बेटी और एक बेटे का परिवार चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। गर्भाशय और अंडाशय होने की बात से मोहल्ले में लोग उनका और परिवार का मजाक भी बना रहे हैं। राजू बताते हैं कि काम बंद होने और समाज में ताने सुनने के तनाव में अब उन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया है।

मानकों पर खरा न उतरने के बावजूद अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज चलता रहेगा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जैसा कि बीते अंकों में लिखा जा चुका है कि मानकों पर खरा न उतरने के चलते नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने इस कॉलेज की मान्यता रद्द करने की जोरदार सिफारिश कर दी थी। विदित है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिये ओपीडी में कम से कम 500 मरीज़ प्रति दिन तथा वार्डों में 360 मरीज़ दाखिल होने चाहिये। इसके अलावा भी अनेकों शर्तें हैं।

एनएमसी ने मई माह में की अपनी जांच में पाया था कि यहां न तो कोई ओपीडी में मरीज़ हैं और न ही कोई वार्डों में दाखिल है। अन्य किसी शर्त के पूरा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने डबल इंजन यानी कि केन्द्र में भी भाजपा सरकार होने का नाजायज लाभ उठाते हुए इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द होने से बचा लिया। इसके लिये राज्य की चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा सिंह ने दिल्ली जाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव से मिल कर अपने इस फ़्लॉप मेडिकल कॉलेज की मान्यता बचा ली। ऐसे अस्पताल में पढ़कर बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे बखूबी समझा जा सकता है। खट्टर सरकार को इससे क्या लेना-देना, उसे तो बतौर फ़ीस 16 करोड़ की आमदनी हो ही जानी है।